उत्पादकता और लुभावने वायदों के परे: भारतीय कृषि और ग्रामीण नीतियों की नयी कल्पना की ओर

ग्रामीण और कृषि अध्ययन नेटवर्क और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन, सितम्बर *26-28, 2019*

प्रेस विज्ञप्ति सितम्बर *29 2019* को जारी

ग्रामीण और कृषि अध्ययन नेटवर्क और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा, सितम्बर ***26-28, 2019*** के दौरान, एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया जिसका शीर्षक था ***"उत्पादकता और लुभावने वायदों के परे: भारतीय कृषि और ग्रामीण नीतियों की नयी कल्पना की ओर"***। इस आयोजन के पीछे यह एहसास था कि विकास के वर्तमान मॉडल में खेती को सिर्फ उत्पादकता के नज़रिये से देखने की प्रवृत्ति अब कारगर नहीं है और इन नीतियों की नयी परिकल्पना की ज़रूरत है। ग्रामीण और कृषि अध्ययन नेटवर्क, शोधकर्ताओं, ज़मीनी कार्यकर्ताओं और किसानों का एक अखिल भारतीय नेटवर्क है जो ग्रामीण भारत की वैकल्पिक रूपरेखा को मुखरित करता है। इस नीति सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य, ग्रामीण भारत को प्रजातांत्रिक और संपन्न बनाने के विभिन्न दृष्टिकोण और मार्गों को एक मंच पर लाना था। सम्मेलन को ***7*** विषयगत सत्रों में बाँटा गया था, और हर सत्र में ग्रामीण भारत से संबंधित बुनियादी मुद्दों का विश्लेषण करने वाले लेखों को प्रस्तुत किया गया। खास बात यह रही कि हर सत्र को एक खुली चर्चा के रूप में आयोजित किया गया था जिनमें किसानों की सक्रिय भागीदारी रही।

सम्मेलन का **सबसे जरूरी सन्देश** है कि गाँव से जुड़ी हमारी नीतियों को, पर्यावरणीय स्थिरता को केंद्र में रख कर, नए सिरे से गढ़ने की ज़रूरत है। कृषि और गाँव एक बृहत पर्यावरण तंत्र का हिस्सा हैं, यह समझाना कृषि और गाँव से जुड़े मुद्दों के इस वैकल्पिक नज़रिये का पहल आयाम होगा। एग्रो-इकोलॉजी *(*कृषि पारिस्थितिकी*)* के सिद्धांतों के ज़रिये, ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय उत्पादन और स्थानीय उपभोग को पर्यावरणीय संरक्षण के धागे के साथ जोड़ा जा सकता है । दृष्टिकोण में इस बदलाव का आधार होगा सह-अस्तित्व । खेतिहर और ग्रामीण भारत की समस्याओं का हल ग्रामीण भारत से नहीं निकलेगा बल्कि ग्रामीण भारत के पर्यावरण, राज्य, उद्योग और शहरी *(*बल्कि वैश्विक*)* उपभोक्ताओं के साथ विपरीत संबंधों को बदलने से निकलेगा। साथ ही साथ, उस विमर्श को भी बदलने की ज़रुरत है जिसने हमारी 'ग्रामीण'की समझ को "पिछड़ेपन"का आकार दिया है।

इस सम्मेलन का **दूसरा मुख्य संदेश** यह है कि जलवायु परिवर्तन के गहराते संकट को देखते हुए, नीति में प्रस्तावित बदलाव और भी महत्वपूर्ण हो जाते है। यह साफ हो गया है कि औद्योगिक युग से पहले के तापमान के मुकाबले हमारी धरती ***1°C*** ज्यादा गरम हो चुकी है, और जलवायु परिवर्तन संबंधित अंतर-देशिय पैनल की रिपोर्ट के हिसाब से ***1.5-2 °C*** की लक्ष्मण रेखा भी जल्द पार हो जाने के आसार हैं। अगर यह लक्ष्मण रेखा लांघी गयी तो, इससे उत्पन्न होने वाली प्रतिक्रियाएँ धरती के पर्यावरण और मानव सभ्यता के विनाश का सामर्थ्य रखती है। जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों के नज़रिये से सबसे संवेदनशील दो इलाकों में से एक है दक्षिण एशिया। इस चुनौती के प्रति हमारी नीतियों को तत्काल ही सजग होने की ज़रूरत है। जलवायु आपात काल दरवाज़े पर दस्तक दे रहा है और इससे निपटने का रास्ता उन्हीं आर्थिक नीतियों में नहीं खोजा जा सकता जो ज्यादा से ज्यादा उपभोग को बढावा देती हैं।

तीसरा प्रमुख संदेश यह है कि ग्रामीण की समस्या का हल ग्रामीण को ही निरर्थक बनाने में नहीं है। हाशिये की तरफ धकेल दिए गए ग्रामीण क्षेत्र के जनसमूहों और व्यवसायों की अपार विविधता को अब और नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता है। इसका अर्थ है कि निर्णय प्रक्रिया को सामूहिक, समावेशी, लोकतांत्रिक और पारदर्शी बनाना होगा। नीति निर्धारण को दिल्ली और राज्यों की राजधानियों की ऊँची इमारतों तक सीमित नहीं रखा जा सकता है, बल्कि लोगों, विशेष रूप से हाशिए के समुदायों, के नज़दीक आकर, उनके मुद्दों और चिंताओं को संबोधित करने की ज़रूरत है। ग्रामीण भारत के स्थानीय समुदायों की टिकाऊ ज्ञान प्रणालियों और प्रथाओं में निहित ज्ञान को हमारी नीति प्रक्रियाओं का आधार कैसे बनाया जाए***?*** हाशिये पर पड़े इस बहुसंख्यक समाज में एक बड़ी संख्या छोटे और सीमांत किसानों, काश्तकारों, आदिवासी समुदायों, वनवासीयों, महिला किसानों, ग्रामीण कारीगरों, घुमन्तु समुदायों, मछुआरों, आदि की है। इन्हें सरकारी मदद की सख़्त ज़रूरत है और नीतियों को इस तरफ ध्यान देना होगा।

चौथा मुख्य संदेश यह है कि इन वैकल्पिक नीति ढाँचों के परिणामों का आकलन पारंपरिक संकेतकों का उपयोग करके नहीं किया जा सकता है। हमें नए संकेतक चाहिए। जब तक हम अपने मापदंडों को नहीं बदलते हैं - क्या गिना जाता है और क्या नहीं - हम ग्रामीण भारत और खासकर खेती, दोनों से ही जुड़े ढांचागत मुद्दों को संबोधित नहीं कर पाएंगे। जब तक हम उपभोग-आधारित विकास के पीछे भागना और जीडीपी में बढ़ोत्तरी को अपना प्राथमिक लक्ष्य मानना नहीं छोड़ेंगे, तब तक हम इस संकट से बहार नहीं आ पाएंगे। क्या हम खेती की उत्पादकता और निपुणता के वैकल्पिक मापदंड खोज सकते हैं***?*** किसानों द्वारा मुहैया करायी जाने वाली पर्यावरणीय सेवाएं, उनके द्वारा संरक्षित कृषि-विविधता, और पैदा किये जाने वाले स्वस्थ्य भोजन का आकलन कर, क्या हम उन्हें इनका भुगतान कर सकते हैं***?*** इन वैकल्पिक मानदंडों के ज़रिये हम अपनी गतिविधियों के सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभावों का मूल्यांकन कर पाएंगे, उनसे होने वाली सकारात्मक और नकारात्मक अंतर-संबंधों को समझ पाएंगे और सही सूचना के आधार पर निर्णय ले पाएंगे।

डॉ अशोक दलवई, सीईओ, नेशनल रेनफेड एरिया अथॉरिटी, ने सभा को संबोधित करते हुए "संपूर्ण अर्थव्यवस्था को एक टर्मिनल प्रणाली से बदलकर एक सर्कुलर प्रणाली में तब्दील करने" का आह्वान किया। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली के निदेशक प्रो रामगोपाल राओ ने ग्रामीण और कृषि अध्ययन नेटवर्क, वैज्ञानिकों और इंजीनियरों जैसे बहु-विषयक समूहों के बीच अधिक बातचीत के नज़रिये समस्याओं और उनके समाधानों की साझा समझ विकसित करने का आह्वान किया। प्रो अंबुज सागर, प्रमुख, स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली ने ज़ोर दिया कि इस वैकल्पिक दृष्टिकोण को व्यवहार में लाने के कार्य में, उपयुक्त नीति प्रक्रियाओं को विकसित करने और जरूरी ज्ञान-नीति संबंधों को समझने की केंद्रीय भूमिका होगी। ग्रामीण और कृषि अध्ययन नेटवर्क की संस्थापक प्रो ए आर वासवी ने अपनी समापन टिप्पणी में हमारे सामने मौजूद समस्या की जटिलता और व्यापकता को देखते हुए तत्काल कदम उठाने की ज़रूरत को दोहराया।

वेबसाइट*:* www.ruralagrarianstudies.org

तस्वीरों सहित सम्मेलन के बारे में अधिक जानकारी:

http://www.ruralagrarianstudies.org/conference/nras-policy-conference-2019/